स्वास्थ्य में निवेश

डॉ मनीषा वर्मा
सिद्धार्थ कुमार

वैश्विक महामारी कोविड-19 के मद्देनजर, एक नया अहसास हुआ है कि मजबूत और लचीली स्वास्थ्य प्रणालियों में निवेश एक समृद्ध राष्ट्र की मजबूत नींव में निवेश के समान है। जैसा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में कहा गया है, भारत विकास संबंधी सभी नीतियों में रोग निरोधी और मुस्तैद स्वास्थ्य सेवा नीति के जरिये प्रभावी और सक्षम स्वास्थ्य रक्षण प्रणाली तैयार करने और "प्रत्येक उम्र में सभी के लिए स्वास्थ्य और कल्याण के उच्चतम संभव स्तर को प्राप्त करने तथा वित्तीय कठिनाई का सामना किए बिना किसी की भी अच्छी गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए प्रतिबद्ध है।"

वर्तमान संदर्भ में 'स्वस्थ लोग, स्वस्थ राष्ट्र' के अलावा कोई अन्य कहावत अधिक महत्व नहीं रखती है। कोविड-19 महामारी ने दुनिया भर में लचीली स्वास्थ्य प्रणालियों में निवेश के महत्व पर बल दिया है। राष्ट्रों को एक बार फिर स्वास्थ्य के समीक्षात्मक महत्व के बारे में याद दिला दिया गया है जो किसी भी समृद्ध और उत्पादक राष्ट्र का शक्तिशाली आधार है।

जब हम स्वास्थ्य प्रणालियों के बारे में बात करते हैं, तो यह एक सामूहिक शब्द की ओर संकेत देता है जो एक-दूसरे से जुड़े विभिन्न घटकों से मिलकर बना है जैसे कि स्वास्थ्य वित्तपोषण और वित्तीय सुरक्षा; स्वास्थ्य सेवा और गुणवत्ता मानदंड; प्रशिक्षित और कुशल मानव संसाधन; स्वास्थ्य का बुनियादी ढांचा; चिकित्सा शिक्षा, प्रभावी नियामक प्रणाली, इक्विटी और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, बहु-हितधारक भागीदारी, सामुदायिक सहभागिता और सुधार तथा कुछ अन्य।

भारत ने वर्षों से मजबूत स्वास्थ्य प्रणालियों और बुनियादी ढांचे को सुनिश्चित करने में निरंतर प्रगति दिखाई है। 2005 में शुरू किए गए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने विभिन्न पहलों और हस्तक्षेपों के लिए अत्यन्त आवश्यक राष्ट्रीय रूपरेखा प्रदान की ताकि सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंडा को आगे बढ़ाया जा सके। हाल के वर्षों में, एक राष्ट्रीय पहल जिसे वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में से एक माना गया है, वह है मिशन इंद्रधनुष। इसका प्रारंभ 25 दिसंबर 2014 को किया गया था और इसे विश्व स्वास्थ्य दिवस, 7 अप्रैल 2015 को उपलब्ध कराया गया। पूर्ण प्रतिरक्षण सुविधा या फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज (एफआईसी) के उद्देश्य से तैयार इस कार्यक्रम को ज्यामितीय विकास में औसतन 1 प्रतिशत वार्षिक टीकाकरण सुविधा में तेजी लाने के लिए पेश किया गया था। 2014 से पहले, राष्ट्रीय

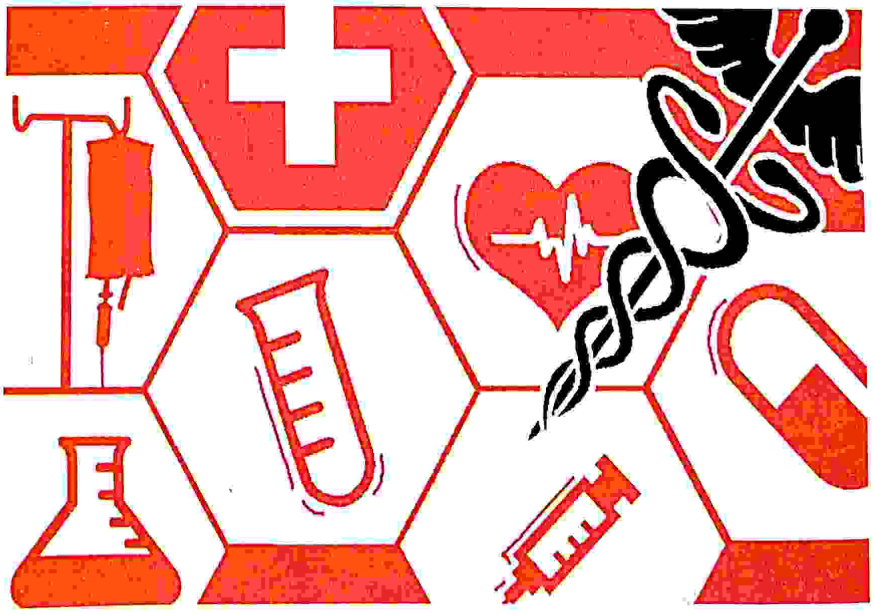

डॉ मनीषा वर्मा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार में अपर महानिदेशक (मीडिया एवं संचार) हैं। ईमेल: pibhealth@gmail.com
सिद्धार्थ कुमार हैल्थ सिस्टम्स स्ट्रेंथनिंग, पीरामल फाउंडेशन में एसोसिएट हैं। ईमेल: sid2804@outlook.com

टीकाकरण सुविधा 1 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ 65 प्रतिशत पर थी। इस गति से, भारत को 90 प्रतिशत टीकाकरण सुविधा प्राप्त करने में 25 वर्ष से अधिक का समय लग जाता। इस सुविधा की दर को तेज करने के लिए, भारत ने 2020 तक 90 प्रतिशत एफआईसी प्राप्त करने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा। सरकार ने गर्भवती महिलाओं और बच्चों दोनों के लिए जीवन चक्र निरंतरता के माध्यम से टीकाकरण सेवाओं को मजबूत किया। जिन सात बीमारियों को लक्षित किया गया उनमें डिप्थीरिया, व्हूपिंग कफ, टेटनस, पोलियोमाइलाइटिस, खसरा, मेनिनजाइटिस और हेपेटाइटिस बी शामिल थे, और इसीलिए इस कार्यक्रम को मिशन इंद्रधनुष (मिशन रेनबो) नाम दिया गया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वार्षिक आधार पर, इस बास्केट में नई चीजों को जोड़ा है। 2016 में, जापानी एन्सेफलाइटिस, रुबेला, निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन (आईपीवी) और रोटावायरस से संबंधित टीके इसमें जोड़े गए, और 2017 में इस कार्यक्रम के अंतर्गत निमोनिया से निपटने के लिए न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन (पीसीवी) को जोड़ा गया। पांच एंटीजनों (डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी [हिब] और हेपेटाइटिस बी) के साथ पेंटावैलेंट वैक्सीन का विस्तार वर्ष 2015 में सभी राज्यों में किया गया था।

हालांकि भारत सरकार ने इस पहल का नेतृत्व किया, डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, रोटरी इंटरनेशनल इत्यादि जैसी अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां मजबूत योजना, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के क्षमता निर्माण, त्वरित व्यवहार परिवर्तन की जानकारी, तथा कार्यक्रम की निगरानी और मूल्यांकन को आगे बढ़ाने के लिए बाहर आए। इस तरह का विस्तृत हस्तक्षेप वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए अनिवार्य था। जबकि वार्षिक टीकाकरण की सुविधा 2016 में प्रति वर्ष 1 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 6.7 प्रतिशत हो गई थी, तीव्र मिशन इंद्रधनुष (मिशन इंद्रधनुष का 5वां चरण) में शामिल किए गए 190 जिलों में किए गए सर्वेक्षण में 2015-16 में कराए गए एनएफएचएस-4 सर्वेक्षण की तुलना में पूर्ण टीकाकरण की सुविधा में 18.5 प्रतिशत अंकों की वृद्धि हुई थी।

इस मिशन के दौरान विभिन्न चरणों में ग्राम स्वराज अभियान और विस्तारित ग्राम स्वराज का कार्यान्वयन भी देखने को मिला। इसने प्रमुख मिशन के साथ सामुदायिक भागीदारी और व्यक्तिगत जुड़ाव को बढ़ाया। जबकि मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) ने लाभार्थियों को जुटाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, प्रेरित सहायक नर्स मिडवाइफ (एएनएम) ने पिछले छह वर्षों में सात चरणों में लगभग 37.6 मिलियन बच्चों और 9.46 मिलियन गर्भवती महिलाओं को टीके लगाए। ये 36 राज्यों और

ईवीआईएन

इलैक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क

भारत में टीकों के स्टॉक और प्रवाह और सभी कोल्ड चेन स्थानों पर भंडारण तापमान के बारे में रियल टाइम यानी वास्तविक जानकारी प्रदान करके टीकाकरण कार्यक्रम की आपूर्ति शृंखला प्रणाली मजबूत बनाना

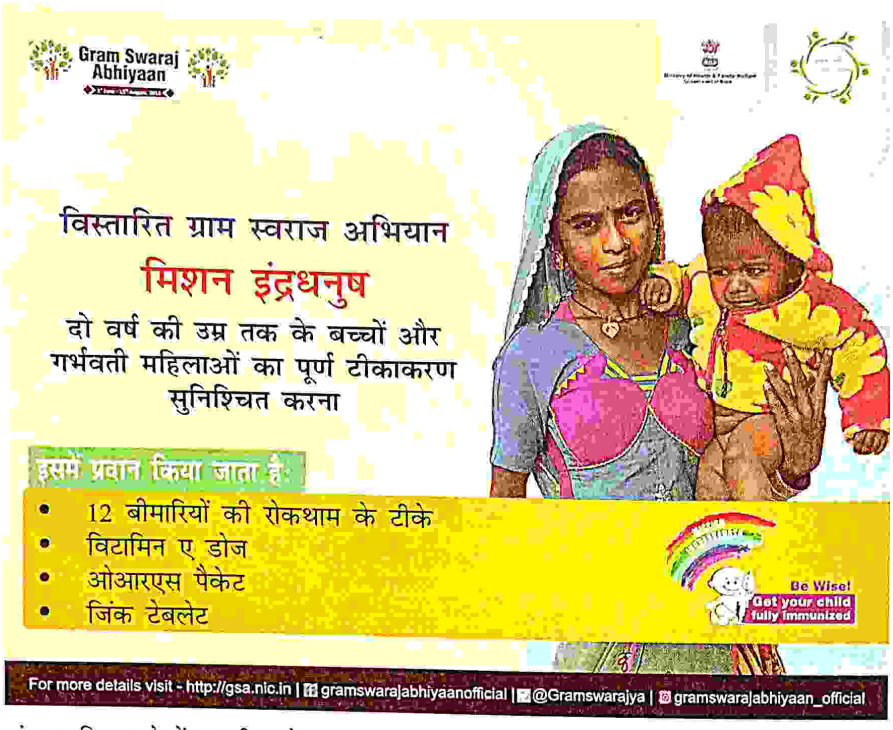

संघ शासित प्रदेशों (यूटी) में लगभग 690 जिलों में फैले हुए हैं। इस प्रकार, आशा और एएनएम जैसे स्वास्थ्य (एचआरएच) संबंधी मानव संसाधनों के सशक्तीकरण ने आज तक मिशन के वाहनों का आवागमन सुनिश्चित किया है। इसलिए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि इस तरह के बेहद सफल सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का दुनिया की 12 सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य कार्य प्रणालियों में से एक के रूप में उचित तरीके से उल्लेखित किया गया है।

इसके अलावा, तीव्र मिशन इंद्रधनुष के बाद के दो चरणों में भी क्रमशः 173 और 272 जिलों में टीके लगाने के काम में तेजी लाई गई। पहले चरण में दिसंबर 2018 तक पूर्ण टीकाकरण (90 प्रतिशत) प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया, आईएमआई के फिर शुरू किए गए दूसरे चरण ने 2019 के मध्य में अधिक संरचित और सामंजस्यपूर्ण तरीके से उड़ान भरी। इन लक्षित हस्तक्षेपों के परिणामस्वरूप, पूर्ण टीकाकरण की सुविधा (एफआईसी) 91.16 प्रतिशत पर (2019-20) पहुंच गई।

टीकों और आपूर्ति शृंखला की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, भारत सरकार ने प्रभावी रूप से देश में ही विकसित ईवीआईएन (इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क) की शुरुआत की, जो तकनीकी समाधानों के माध्यम से टीकों और कोल्ड चेन रखरखाव की आपूर्ति सुनिश्चित करता है। यह देश के सभी 27,000 कोल्ड चेन बिंदुओं पर टीकों के स्टॉक और प्रवाह, और भंडारण तापमान (2-8 डिग्री सेंटीग्रेड पर बनाए रखने के लिए) के बारे में वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करता है। यूएनडीपी के साथ, इस पहल से 90 मिलियन टीका संबंधी खुराक को बचाने में सफलता मिलने के साथ टीकों की आपूर्ति और तापमान मानदंडों को बनाए रखने की 99 प्रतिशत अनुपालन दर रही है, जिससे भारत में टीकाकरण कार्यक्रम की सुविधा और गुणवत्ता में सुधार हुआ है। इसके लाभों को देखते हुए, ईवीआईएन इंडोनेशिया, सूडान और मलावी जैसे देशों का सफलतापूर्वक मार्गदर्शन कर रहा है।

हाल के वर्षों में, केन्द्र सरकार का एक प्रमुख प्रमुख कार्यक्रम जिसने बड़े पैमाने पर आकर्षित किया है, आयुष्मान भारत (एबी) कार्यक्रम है, अपने स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती केन्द्रों (एचडब्ल्यूसी) के जुड़वां स्तंभों के साथ, जो प्राथमिक और माध्यमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करते हैं, और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जिसमें सबसे कमजोर और जरूरतमंद आबादी (लगभग 10.74 करोड़ गरीब और वंचित ग्रामीण परिवारों जिसमें लगभग 50 करोड़ लोगों को शामिल किया गया है जिसमें जनसंख्या पिरामिड के नीचे के 40 प्रतिशत लोग शामिल हैं) के लिए स्वास्थ्य बीमा का प्रावधान किया गया है। पीएमजेएवाई को 23 सितंबर 2018 को शुरू किया गया था और इसमें दुनिया की किसी भी स्वास्थ्य बीमा योजना के मुकाबले विशालतम जनसंख्या को योजना में शामिल किया गया है।

प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को व्यापक स्तर पर लाभार्थियों के दरवाजे तक लाने की कोशिश में, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती केन्द्र (एबी-एचडब्ल्यू-सी) योजना में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लाभार्थियों के रूप में समुदायों को शामिल करने में एक कदम आगे हैं। इसके अतिरिक्त, इसमें मातृ और बाल स्वास्थ्य और गैर-संचारी रोगों दोनों से संबंधित सेवाओं को शामिल

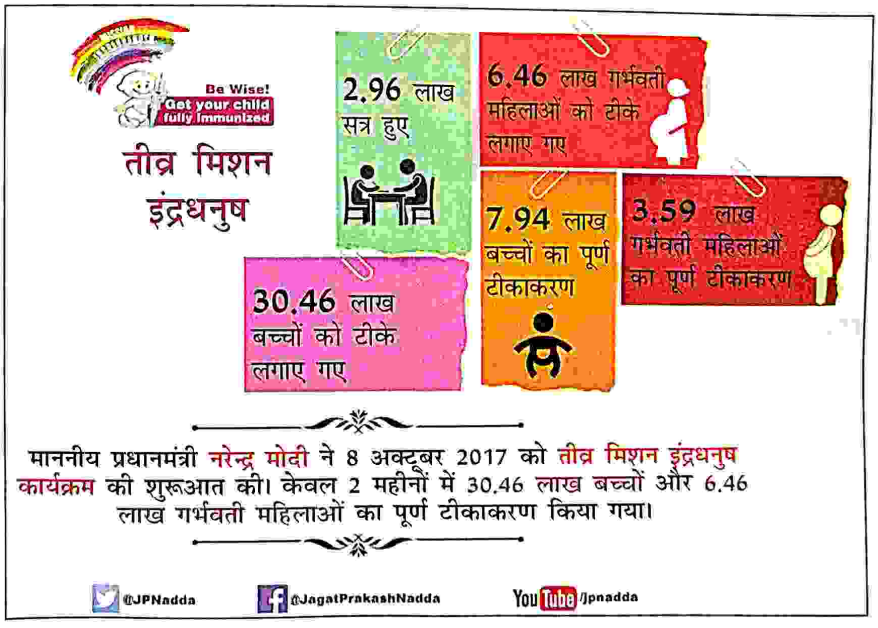

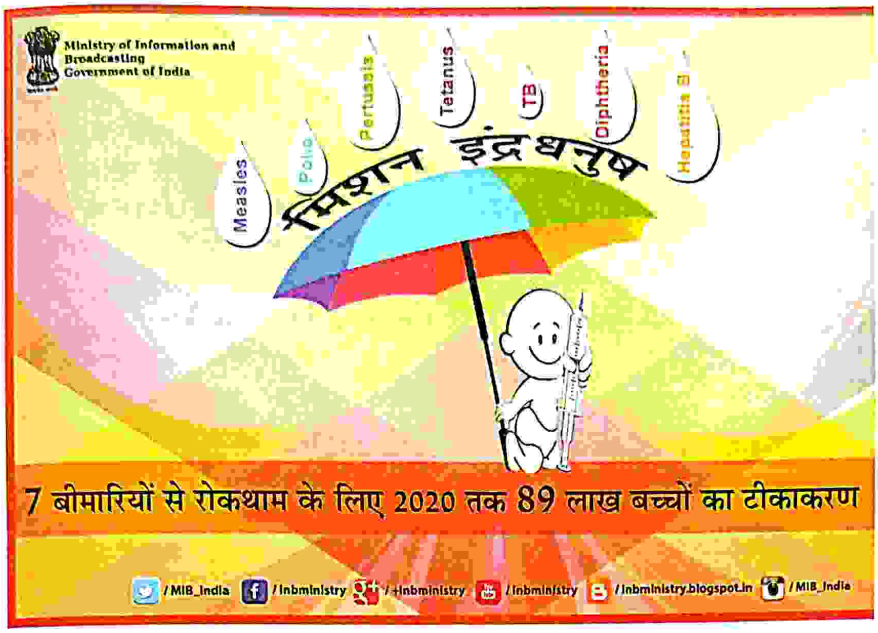

किया गया है। उप-केन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केन्द्रों के विकासमूलक मॉडल, एचडब्ल्यूसी को व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए उत्कृष्टता केन्द्र बनने के लिए तैयार किया गया है। सामुदायिक भागीदारी, संस्थागत सुधारों और दवाओं और टीकों की मुफ्त पहुंच के साथ, एचडब्ल्यूसी आज भारत में मजबूत स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का एक प्रमुख हिस्सा है। इसके अलावा, यह निश्चित रूप से मौजूदा स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में सुधार करेगा और हमारे देश के ग्रामीण, दूरदराज के क्षेत्रों और ऐसे इलाकों में नई स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करेगा जहां पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। अब तक, 40,644 एबी-डब्यूक सी काम करने लगे हैं जिसमें एक निश्चित समय पर कुल 15.79 करोड़ लोग जा चुके हैं जिसमें 8.56 करोड़ महिलाएं हैं। इसके अलावा, 4.23 करोड़ लोगों की उच्च रक्तचाप के लिए जांच की गई; मधुमेह (डायबिटीज) के लिए 3.55 करोड़; स्तन कैंसर के लिए 1.25 करोड़; और सर्वाइकल कैंसर के लिए 82.54 लाख लोगों की जांच की गई। योग के 11 लाख से अधिक सत्र भी एचडब्ल्यूसी में आयोजित किए जा चुके हैं।

आयुष्मान भारत का दूसरा भाग, पीएमजेएवाई में, अस्पताल में भर्ती होने संबंधी तृतीयक देखभाल के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के अलावा, देश में न केवल बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं और स्वास्थ्य प्रणालियों का दायरा बढ़ाया है, बल्कि उसे पिछले कुछ वर्षों में सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में बजटीय आवंटन की कथित कमी के लिए भी बनाया गया है। सरकार ने निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के अस्पतालों में इस कार्यक्रम के साथ 23 विशिष्ट सेवाओं को भी शामिल किया है, इस प्रकार निजी क्षेत्र के अस्पतालों के यूएचसी को योगदान पर चर्चा को फिलहाल खत्म कर दिया है। वास्तव में, यह कार्यक्रम सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र के लक्ष्यों के साथ निजी क्षेत्र के अस्पतालों को श्रेणीबद्ध करने में उपयोगी होगा। हाल के आंकड़ों से संकेत मिलता है कि 12.46 करोड़ लाभार्थियों को योजना कार्ड प्रदान किए गए हैं; 21,583 अस्पतालों को सूची में सम्मिलित (एमपैनल) किया गया है; 1 करोड़ से अधिक लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया (1 जून 2019 तक 70.9 लाख) और लाभार्थियों को 13560.72 करोड़ रुपये इलाज के लिए प्रदान किए गए। इसके अलावा, अस्पताल में 1.05 लाख से अधिक दाखिलों को दूसरी जगह पर लाभ लेने (पोर्टेबिलिटी) के तहत अधिकृत किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा 24 अगस्त 2018 को एक राष्ट्रीय कॉल सेंटर (टोल फ्री नंबर-14555) स्थापित किया गया, जिसमें 20 लाख आने वाले (इनबाउंड) और 70 लाख बाहर जाने वाले (आउटबाउंड) कॉल दर्ज किए गए हैं।

सरकार ने गर्भवती महिलाओं और बच्चों दोनों के लिए जीवन चक्र निरंतरता के माध्यम से टीकाकरण सेवाओं को मजबूत किया। जिन सात बीमारियों को लक्षित किया गया उनमें डिप्थीरिया, व्हूपिंग कफ, टेटनस, पोलियोमाइलाइटिस, खसरा, मेनिनजाइटिस और हेपेटाइटिस बी शामिल थे, और इसीलिए इस कार्यक्रम को मिशन इंद्रधनुष नाम दिया गया।

पीएमजेएवाई के प्रत्यक्ष लाभ हर किसी के देखने के लिए स्पष्ट तौर पर पर्याप्त हैं। हालांकि यह निश्चित रूप से यूएचसी को प्राप्त करने के लिए भारत के अभियान को आगे बढ़ाने में सहायक होगा, यह विशेष रूप से हमारे सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) और एसडीजी-3 (अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण) की प्राप्ति में सकारात्मक प्रभाव डालेगा। इस हिस्से का एक और मुख्य आकर्षण यह है कि यह चिकित्सा देखभाल और स्वास्थ्य सेवाओं को सुरक्षित करने के लिए स्वास्थ्य सेवा पर मरीज अथवा उसके परिवार द्वारा स्वास्थ्य सेवा प्रदाता प्रत्यक्ष तौर पर दिए जाने वाले खर्च को कम करने के लिए बाध्य है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रमुख आयाम जिनमें भारत ने पिछले छह वर्षों में विशाल प्रगति की है, वह है प्रजनन संबंधी बाल स्वास्थ्य (आरसीएच) कार्यक्रम। सभी प्रमुख आरसीएच संकेतकों अर्थात् मातृत्व मृत्यु दर (एमएमआर), नवजात मृत्यु दर (एनएमआर), शिशु मृत्यु दर (आईएमआर), पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चे की मृत्यु दर (यू-5 एमआर) और कुल प्रजनन दर (टीएफआर) आदि ने संतोषजनक सुधार दर्ज किया है। इन्होंने हमें भारत में स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों की तीव्र और संपूर्ण प्रगति के बारे में महत्वपूर्ण सबूत प्रदान किए हैं। उस विशेष क्षण के दौरान जब स्वास्थ्यगत प्रणालियां बढ़ रही थी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

में नीति निर्माताओं ने अप्रैल 2015 में लक्ष्य हासिल करने के लिए मातृ और नवजात टेटनस उन्मूलन (एमएनटीई) सत्यापन को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया। मार्च 2014 में पोलियो उन्मूलन हासिल करने के बाद यह भारत सरकार को गौरवान्वित करने वाली एक उपलब्धि थी।

इस अवधि के दौरान, भारत ने नवजात शिशु देखभाल पर अत्यधिक जोर दिया, इसलिए भारत में विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाइयों (एसएनसीयू) को बढ़ाना बेहतर नवजात शिशु और शिशु स्वास्थ्य देखभाल के काम में सबसे आगे रखा गया। जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में 794 एसएनसीयू की स्थापना के साथ, एसएनसीयू में उपलब्ध कराई गई चौबीस घंटे की इन सुविधाओं में प्रतिवर्ष 0.85 मिलियन लाभार्थियों को भर्ती किया जा रहा है। इस प्रमुख पहल के साथ, भारत में बच्चों की स्वास्थ्य सेवा में सुधार करने के लिए अन्य हस्तक्षेपों का अत्यन्त, महत्व है। जन्म के समय विटामिन 'के' के इंजेक्शन का सार्वभौमिकीकरण, समय पूर्व प्रसव के दौरान प्रसव पूर्व कॉर्टिकॉस्टिरॉयड्स, कंगारू मदर केयर (केएमसी) और एएनएम द्वारा नवजात शिशुओं को जेंटामाइसिन का टीका लगाना ताकि नवजात शिशुओं का इलाज किया जा सके; इन सभी ने पिछले छह वर्षों में भारत में बहुत से नवजात और शिशुओं को बचाने की संभावनाओं को बढ़ा दिया है। इस तरह के गहरा असर डालने वाले हस्तक्षेप नवजात शिशुओं को अन्य बीमारियों के अलावा सेप्सिस, पेरीवेन्ट्रिकुलर और इंट्रावेंट्रिक्युलर हेमरेज, बर्थ एस्फिक्सिया, निमोनिया, डायरिया आदि से बचाते हैं।

मातृ स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की एक प्रमुख नीतिगत सफलता जून 2016 में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्वे अभियान (पीएमएसएमए) के कार्यान्वयन के साथ सामने आई। इस कार्यक्रम के तहत, हमारे देश की सभी गर्भवती महिलाओं को निजी क्षेत्र की भागीदारी से हर महीने की 9 तारीख को निश्चित और मुफ्त प्रसव पूर्व देखभाल (एएनसी) सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इससे न केवल प्रसवपूर्व देखभाल की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिलती है, बल्कि एकदम शुरुआत में उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था की पहचान करने में भी मदद मिलती है। अब तक, 2.44 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं को विशेष एएनसी जांच से लाभ मिला है; 1.26 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं को पहली बार दूसरी/तीसरी तिमाही में पीएमएसएमए सेवाएं मिली हैं; 12.8 लाख से अधिक उच्च जोखिम वाले गर्भवती महिलाओं की पहचान की गई है और 6301 से अधिक निजी क्षेत्र के स्वयंसेवकों ने पीएमएसएमए के तहत स्वैच्छिक सेवाएं प्रदान करने के लिए पंजीकरण कराया है।

मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) ने लाभार्थियों को जुटाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, प्रेरित सहायक नर्स मिडवाइफ (एएनएम) ने पिछले छह वर्षों में सात चरणों में लगभग 37.6 मिलियन बच्चों और 9.46 मिलियन गर्भवती महिलाओं को टीके लगाए।

भारत सरकार के प्रमुख विचार मंच नीति आयोग ने भारत सरकार के 'आकांक्षापूर्ण जिलों की कायापलट' (टीएडीपी) कार्यक्रम के कार्यान्वयन और निरीक्षण में प्रमुख भूमिका निभाई है। हालांकि इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के उन पिछड़े 117 जिलों का उत्थान करना है जो स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और बुनियादी ढांचे के विशिष्ट विकास मापदंडों में पिछड़ रहे हैं, इस बारे में गौर करना दिलचस्प है कि इस कार्यक्रम के छह मुख्य विषयक क्षेत्रों में अधिकतम प्रतिनिधित्व (30 प्रतिशत) स्वास्थ्य और पोषण को दिया गया है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि भारत सरकार को उम्मीद है कि इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन से मजबूत स्वास्थ्य प्रणालियां तैयार की जाएंगी।

वैश्विक महामारी कोविड-19 के मद्देनजर, एक नया अहसास हुआ है कि मजबूत और लचीली स्वास्थ्य प्रणालियों में निवेश एक समृद्ध राष्ट्र की मजबूत नींव में निवेश के समान है। जैसा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में कहा गया है, भारत विकास संबंधी सभी नीतियों में रोग निरोधी और मुस्तैद स्वास्थ्य सेवा नीति के जरिये प्रभावी और सक्षम स्वास्थ्य रक्षण प्रणाली तैयार करने और "प्रत्येक उम्र में सभी के लिए स्वास्थ्य और कल्याण के उच्चतम संभव स्तर को प्राप्त करने तथा वित्तीय कठिनाई का सामना किए बिना किसी की भी अच्छी गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए प्रतिबद्ध है"। इसे स्वास्थ्य रक्षण सेवा तक बढ़ती पहुंच, गुणवत्ता में सुधार और खर्च को कम करके हासिल किया जा सकता है। ■

संदर्भ

1. https://main.mohfw.gov.in/sites/default/files/04»20ChapterAN2018-19.pdf